The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 3 | March 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

उच्च शिक्षा परिदृश्य में परिवर्तन: एनईपी 2020 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

ज्योत्सना

असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालजी, गोलापार, हल्द्वानी

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :

नई शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा

ABSTRACT

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है। एनईपी 2020 भारत में उच्च शिक्षा को 21 वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी, जिससे अमीर-गरीब विभाजन कम हो जाएगा और देश में दीर्घकालिक ज्ञानात्मक समाज में परिवर्तन होगा। भारत में विश्व स्तरीय प्रारंभिक, मध्यवर्ती, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया, इसका उद्देश्य सक्रिय, उत्पादक, जानकार और नैतिक नागरिकों को बनाना है जो निष्पक्ष और समावेशी समाज के विकास में योगदान देंगे। एनईपी 2020 विद्यार्थी केंद्रित है, जो उन्हें अपने रुचि व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन देता है और उनके कौशल को विकसित करता है, जिससे वे अधिक रोजगारपरक बन सकें। एनईपी 2020 ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भविष्य में आवश्यक क्षमताओं की योजना बनाई है। एनईपी 2020, जो शिक्षा को सुलभ,

समतावादी और समावेशी बनाने पर केंद्रित है, निस्संदेह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लक्ष्य में काफी मदद करेगा, लेकिन यह सिर्फ तब होगा जब यह सभी स्तरों पर ठीक प्रकार से लागू किया जाएगा। यह लेख एनईपी 2020 के उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है

परिचय:- भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा से ब्रिटिश शिक्षा तक शिक्षा प्रणाली में कई सुधार और संशोधन किए गए हैं। 1968में पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी, फिर 1986 में दूसरी और 1992 में दुसरी शिक्षा नीति को कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया गया। तब से, पिछले 34 वर्षों में हमने इसी शैक्षिक नीति का पालन किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (National Education Policy 2020) को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी नीति (NEP1986) को प्रतिस्थापित करती है। भारत सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी और लागू किया है। यह नई नीति "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020)" कहलाती है। यह भारत की भविष्य की शिक्षा प्रणाली के लिए लक्ष्य को परिभाषित करती है और ग्रामीण और शहरी दोनों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य "हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समतामूलक, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करना, और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञानात्मक समाज बनाना है। इस तरह यह भारत को एक वैश्विक ज्ञानात्मक महाशक्ति बनाता है। सन् 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति बनाई गई जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सुझावों पर आधारित थी, इसमें सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा को सुधारने और समान शैक्षिक अवसरों की सिफारिश की साथ ही उन्होने शिक्षा पर खर्च को राष्ट्रीय राजस्व का 6% तक बढ़ाने की बात कही। इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु उसमें सुचना प्रौद्योगिकी को शामिल किया साथ ही शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, महिला सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति के विस्तार, पिछड़े और ग्रामीण समुदायों के लिए प्रावधान और वयस्क साक्षरता को नया स्वरूप देने पर अधिक जोर दिया गया है। इसके पश्चात् 1992

में इसमें पुन: कुछ संशोधन किये गये। इसने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता देने से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी हालाँकि यह रोजगार योग्य कौशल वाले स्नातक तैयार करके शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में विफल रहा। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत की तीसरी शिक्षा नीति (NEP-2020)का प्रस्ताव जारी किया। इस पर व्यापक बहस हुई और **29 जुलाई, 2020** को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। इसने पाठ्यक्रम को बदलकर अधिक विश्लेषण-आधारित, चर्चा-आधारित और अनुभव-आधारित शिक्षा का प्रावधान किया। इसमें शैक्षणिक संरचना में कई अन्य बदलावों का भी उल्लेख है। आजादी के बाद संविधान ने कहा कि 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। यहां तक कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE-2010) और पिछली दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी ऐसा कहा गया है, हालाँकि एक देश के रूप में हमें अभी भी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में उच्च शिक्षा (HE) प्रणाली के विखंडन के कुछ कारण हैं- छात्रों को आकर्षित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुँच का अभाव, करियर के लिए अपर्याप्त तंत्र, बुनियादी ढांचे और संस्थागत स्वायत्तता की कमी, मानव अनुसंधान और नवाचार की कमी, विश्वविद्यालयो, कॉलेजों और संकाय भर्ती मानकों में कमी। इसलिए इसे बदलने के लिए एक नई नीति की आवश्यकता थी। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन जरूरतों को पूरा करती दिखती है। अच्छे विचारशील सर्वांगीण और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना इस नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य है। यह एक व्यक्ति को उसकी रुचि के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाने, साथ ही बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को भी विकसित करने, भाषाओं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में पारंगत बनाने के लक्ष्य के साथ प्रस्तुत की गई है। यह निश्चित रूप से हमारे देश को एक गतिशील ज्ञानात्मक समाज में बदल देगा, जहां हर व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा।

साहित्य समीक्षा -: पिछले शोध अध्ययन भी सरकार के इस कदम को सराहते हैं। ऐथल और ऐथल (2020) ने पाया कि "देश के नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिये प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षा में शामिल करना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है।" ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता, आकर्षण और सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के नियम प्रस्तुत करती है। पवन कल्याणी (2020) का मानना है कि "एनईपी-2020

में नियमित पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे सही समय पर सही कौशल प्राप्त करने के लिए कई नई चीजें प्रस्तावित हैं, अगर छात्र जन्मजात प्रतिभा के अनुसार सही पाठ्यक्रम या विषय संयोजन चुनते हैं तो भविष्य में उद्योग और शिक्षा क्षेत्रों के बीच की अन्योन्यता को समाप्त किया जा सकता है। दीप कुमार (2020) ने इसका स्वागत करते हुए कहा, "नई नीति का उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। यह देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत जरूरी सुधार लाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक है। डॉ. के. मीनाक्षी सुंदरम (2021) के अनुसार, 2020 की शैक्षिक नीति में डिजिटल शिक्षा, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की स्वायत्तता और वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और शिक्षा की उन्नति के साथ बहु-विषयक दृष्टिकोण के लिए अत्यधिक संभावनाएँ हैं, जो समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कुमार और नागरानी (2020) ने अपने लेख मे कहा कि, "नई शिक्षा नीति इस देश में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक महान दृष्टिकोण है"। फिक्की-ईवाई (2021) रिपोर्ट के अनुसार, "नीति वर्तमान स्थिति में अंतराल की पहचान करती है और सुधारों का सुझाव देती है जो प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों से उच्च शिक्षा के माध्यम से उच्चतम गुणवत्ता, समानता और अखंडता लाने के लिए किए जा सकते हैं"। झिंगन एट अल (2020) ने अपने शोध लेख में स्पष्ट किया कि "एनईपी-2020 की शुरूआत और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियामक व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार भारत के भीतर उच्च शिक्षा खंड को पुनर्जीवित और सुव्यवस्थित करने के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके वास्तविक परिणाम प्रस्तावित नीति के जमीनी स्तर के कार्यान्वयन पर निर्भर करेंगे। उपरोक्त शोध लेखों के विवेचन से पता चलता है कि एनईपी-2020 उच्च शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। हालाँकि, इसे वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने के लिए एक निश्चित समय और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा प्रावधान -: उच्च शिक्षा मानवता और सामाजिक कल्याण के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का उद्देश्य भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानवीय देश बनाना है, जहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हर आदमी में होगा। एक देश के आर्थिक विकास और आजीविका को स्थायित्व देने में उच्चतर शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जाएगा, उतनी ही संख्या में युवा भारतीय उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। गुणात्मक शिक्षा से व्यक्तिगत ज्ञान, रचनात्मकता, सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को आर्थिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे वे अपनी जीवनशैली और नौकरी में अधिक सफल और खुश हो सकें। पूर्व- विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक, शिक्षा के प्रत्येक चरण में व्यक्ति के समग्र

विकास के लक्ष्य के लिए कौशल और मूल्यों का एक निश्चित सेट शामिल होना चाहिए। साथ ही, उच्चतर शिक्षा देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो नवाचार और ज्ञान का आधार है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ रोज़गार के अवसर पैदा करना नहीं है, बल्कि एक अधिक खुशहाल, समृद्ध, सुसंस्कृत, उत्पादक, नवीन, प्रगतिशील और समृद्ध देश बनाना है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP2020) ने शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति का स्थान लिया है और यह 'पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही' के स्तंभों पर आधारित है और यह भारत को एक जीवंत ज्ञान केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखती है। NEP-2020 का लक्ष्य है कि दो करोड़ वंचित स्कूली छात्रों को मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में शामिल किया जाए अत: स्कूल में 5+3+3+4 उम्र 3-8, 8-11 और 14-18 के नए पाठ्यक्रम ढांचे को 10+2 प्रणाली से बदल दिया गया है तथा पांचवीं कक्षा तक पहुंचने तक विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च शिक्षा के सभी स्कूलों और संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। "2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा"। NEP2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश की जीडीपी(GDP) के 6% हिस्से के बराबार निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 में मुख्य प्रावाधान निम्न प्रकार से हैं।

(1) बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी)Multiple Entry & Exit)

वर्तमान में 3या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढाई छोड़ देता है, तो उसे डिग्री ना मिलने से उसकी उस पढ़ाई का महत्व नहीं रह जाता लेकिन नई शिक्षा नीति में इसमें निम्न परिवर्तन हैं। 2020

Sr.No	Option	Academic Recognization
1.	Ist year of UG Program	Certificate
2.	IInd year of UG Program	Diploma
3.	IIIrd year of UG program	Degree
4.	IVth year of UG program	Bachelor's with research

(2) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit)-:

- ❖ इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रुप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलगअलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर - प्रमाणपत्र दिया जायेगा।
- ❖ जो छात्र हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते उनके लिये स्नातक)UG) अब साल 3 का होगा, किंतु शोध अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये साल का। 4
- ❖ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा साल 5 का सयुंक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जायेगा।

(3) कॉमन एडमिशन टेस्ट ,CAT(Common Admission Test) :-

- ❖ ऊच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये कामन एग्जाम होगी जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी।
- ❖ संस्था के लिये यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नहीं है।
- ❖ वर्तमान में केंद्रिय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय सबके अपने अलग नियम हैं अब सबमें एक समान नियम बनाया जायेगा।

(4) अंतरराष्ट्रीयकरण (Internationalization) :-

- ❖ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा, साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
- ❖ विश्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिल फॉर टैक्निकल एजुकेशन को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जायेगी।

एनईपी 2020 की उच्च शिक्षा की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -:

1. अंत: विषय प्रशिक्षण -: एनईपी 2020 में विभिन्न शैक्षणिक विषयों और संकायों के बीच कठोर सीमाएँ समाप्त कर दी जाएंगी। यह विश्वविद्यालयों को बहुविषयक पाठ्यक्रमों को पेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है, जो विद्यार्थियों को अध्ययन के विभिन्न विषयों और क्षेत्रो में प्रवेश लेने की अनुमति देता है।

2. लचीला पाठ्यक्रम -: एनईपी 2020 ने एक लचीले पाठ्यक्रम की सिफारिश की है जो छात्रों को कई विषयों और पाठ्यक्रमों को अपनी रुचि के अनुरुप चुनने का अवसर देता है, ताकि छात्र अपने करियर

और व्यक्तिगत हितों को पूरा कर सके। नई शिक्षा नीति एक क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली का प्रस्ताव रखती है, जिसमें छात्रों को एक संस्था से दूसरे संस्था में स्थानांतरित करने पर उनके क्रेडिट नये संस्था में जोड दिये जायेंगे, जिससे शिक्षा को गतिशीलता और उत्कृष्टता बढ़ती है।

3: खोज और नवाचार -: एनईपी 2020 का लक्ष्य भारत को नवाचार और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है, साथ ही विश्वविद्यालयों को अनुसंधान को प्राथमिकता देने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। नई शिक्षा नीति सभी विषयों में अनुसंधान का समर्थन और वित्तपोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की सिफारिश करती है।

4: व्यावसायिक कौशल विकास -: एनईपी 2020 ने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण बताया है। यह व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षण और कार्य-एकीकृत शिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव करती है, जो विद्यार्थियों को संबंधित कौशल हासिल करने में मदद करेंगे।

5: ऑनलाइन पढ़ाई -: एनईपी 2020 ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी का महत्व स्वीकार करते हुए व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे की सिफारिश की है। यह विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और मिश्रित शिक्षण प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो शिक्षा तथा विद्यार्थियों तक पहुंच बढ़ाता है।

6: समानता और समावेशिता -: एनईपी 2020 ने बालिकाओं, कम आय वाले परिवारों और विकलांग छात्रों जैसे वंचित समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने पर बल दिया है। यह सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समान अवसर देने की कोशिश करता है।

7: वैश्वीकरण -: एनईपी 2020 का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना और संकाय और छात्र आदान-प्रदान की सुविधा देना। नीति राज्यों के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम (NEP) की स्थापना की सिफारिश करती है।

8: स्वतंत्रता और जिम्मेदारी -: एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा की प्रभावशीलता और गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत स्वायत्तता और निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने का सुझाव दिया है। नीति ने

नियामक निकायों को जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।

उपसंहार-: शिक्षा सामाजिक विकास और उन्नति में एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षित व्यक्ति का समाज में योगदान अधिक लाभदायक होता है। शिक्षा एक उपकरण है जो लोगों को देश और समाज के प्रति उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए ज्ञान, जानकारी, कौशल और तकनीक प्रदान करता है। 34 वर्षों के लम्बे इंतजार के बाद देश को 2020 में नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई। जिसका लक्ष्य देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर दीर्घकालिक लाभकारी प्रभाव डालना है। यह नीति सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू करती है और मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भविष्य के अपेक्षित परिणामों पर मजबूत पकड़ रखती है। एनईपी-2020 कृषि से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा करती है। यह नीति व्यापक है और इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं। यह नीति शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाती है और देश के व्यापार और आर्थिक विकास को पूरा करती है। एनईपी-2020 भारत को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु और सभी इच्छुक शिक्षकों और छात्रों के लिए आवश्यक क्षमताओं के साथ तैयार होने का मार्ग प्रसस्त करती है। इस नीति की दृष्टि से, “भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित, सूचना केंद्रित से ज्ञान केंद्रित, अंक केंद्रित से कौशल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित से प्रयोगात्मक केंद्रित, शिक्षण केंद्रित से अनुसंधान केंद्रित और विकल्प केंद्रित से योग्यता केंद्रित हो रही है।” (ऐथल और ऐथल)। नई शिक्षा नीति में एक सराहनीय दृष्टिकोण है, लेकिन इसकी प्रभाविता इसके कार्यान्वयन से निर्धारित होगी। यदि यह सही ढंग से लागू किया गया तो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली निश्चित रूप से विश्वस्तरीय स्तर पर स्थानांतरित हो जाएगी|

REFRENCES

Anonymous:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

Anonymous: https://www.education.gov.in/nep/about-nep.

Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, *5*(2), 19-41.

FICCI(2021). Higher Education in India: Vision 2040. FICCI www.cci hes.com/pdf/2021/eyreport.pdf.

Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. *University of South Florida (USF) M3 Publishing*, *3*(2021), 36.

Kumar, B. V. D. S. S. P., & Nagrani, K. (2020). The Study of New Education Policy 2020. *International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), 8 (10), 527*, *528*.

Kumar, D. (2020). A critical analysis and a glimpse of new education policy-2020. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, *11*(10), 248-253.

Kalyani, P. (2020). An empirical study on NEP 2020 [National Education Policy] with special reference to the future of Indian education system and its effects on the Stakeholders. *Journal of Management Engineering and Information Technology*, *7*(5), 1-17.

Nawale, A. M., & Nawale, A. A. (2022). National Education Policy-2020 and Higher Education: A Road towards Reform. University News, 60(07), February 14-20, 2022.

Sundaram, M. K. (2020). National Education Policy 1986 vs National Education Policy 2020–a Comparative Study. *International Research Journal on Advanced Science Hub*, *2*(10S), 127-131.

Umachagi, A. E., & Selvi, R. (2022). National education policy 2020 and higher education: A brief review. *Sumedha Journal of Management*, *11*(2), 19-26.